

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 03 सितम्बर 2025, समय 1305 (5 मिनट)

यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के मद्देनजर फरीदाबाद प्रशासन ने यमुना किनारे बसे गांवों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी कुछेक स्थानों पर पानी आया है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने कल देर शाम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उपायुक्त ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित गांवों से सैकड़ों परिवारों को प्रशासनिक टीमों की मदद से निकाला गया है। इन्हें अस्थायी शिविरों में ठहराया गया है, जहां खाने-पीने और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने घर में रह गए लोगों से भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल और पुलिस की टीम लगातार गांवों में गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जो लोग घर नहीं छोड़ रहे उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें जबरदस्ती वहाँ से निकाला जाएगा।

श्री विक्रम सिंह ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उधर रेडक्रॉस के सचिव बिजेंद्र सरोत ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वयंसेवकों को तैयार रहने को कहा है।

भिवानी के गांव कलिंगा में भारी बरसात से रात को एक मकान गिर गया। मकान में सो रहा पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। प्रशासन द्वारा गांव

वालों की मदद से परिवार के सभी 6 सदस्यों को मलबे से निकाला गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण सभी सदस्यों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। परिषद द्वारा भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है, जिसमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इस बैठक में भाग ले रहे हैं।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा है कि हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दायर की गई याचिका को कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, वैध एवं न्यायसंगत है। श्री हिम्मत सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा-CET में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य सदैव सभी अभ्यर्थियों के साथ निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना रहा है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर लागू किया गया है ताकि सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक जैसे पैमाने पर हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के संजान में यह बात आई है कि इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया, जिसके कारण उन्होंने अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया में समय और धन खर्च किया। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी

भी तरह की भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिसूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।

पलवल के राजकीय आई.टी.आई. में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत आज एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता संतराम डागर ने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रणाली न केवल सुरक्षित और पारदर्शी है बल्कि आमजन को शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे अनेक लाभ भी उपलब्ध कराती है।
